(a) whether according to latest report of the World Health Organisation 1.5 million people in India become sick with TB each year;

(b) if so, how do these figures compare with Government's assessment indicating the rural and urban victims of TB each year; and

(c) what is the plan of action of eradication of TB under the Eighth Plan and the achievements made thereunder so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) and (b) The number of TB cases detected and put on treatment during the last five years are as under:—

Year	TB Casese detected
1990-91	15.99 lakhs
1991-92	12.79 lakhs
1992-93	15.39 lakhs
1993-94	13.59 lakhs
1994-95	12.49 lakhs

It is estmated that 76% cases are found in rural areas.

(c) The National Tuberculosis Control Programme launched by the Government in 1962 has succeeded in reducing mortality rate. Childhood TB and serious form of Tuberculosis in adults are on the decline. The special efforts being made to combat the disease are by expanding the National Tuberculosis is Control Programme and through its effective implementation. A revised strategy to detect TB cases through quality miscroscopy and to achieve 85% cure rate among new sputum positive cases and Directly Observed Therapy (DDT) of more effective short course chemotherapy is being tested in selected project areas in fine districts and ten cities.

गुजरात में लम्बित मामले तथा न्यायाधीशों के रिक्त पड़े हुये पद

2361. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1995 की तिथि के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय में कुल कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) ऐसे लम्बित मामलों का जिला-वार एवं श्रेणी-वार क्या है;

(ग) 30 जून, 1995 की तिथि को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त थे;

(घ) क्या गुजरात उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों के पदों के लिये उम्मीदवारों की कोई सूची प्राप्त हुई है; और

(ङ) इन पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) 30 जून, 1995 को गुजरात उच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामले लम्बित थे:—

सिविल मामले	— 77721
दांडिक मामले	— 11019
प्रकीर्ण मामले	— 5613
योग	— 94353

गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि लम्बित मामलों की जिला-वार जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है।

(ग) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय में 30 स्थायी (अपर न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से स्थायी) अपर न्यायाधीशों के 7 पद रिक्त थे।

(घ) और (ङ) गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और उन पर सक्रियता के विचार किया जा रहा हैं।